20 हजार युवाओं को मिलेगा रोजगार, करोड़ों की जमीन को मुक्त कराएगी उत्तर प्रदेश सरकार

प्रतापगढ़ में एटीएल की जमीन पर बनेगा निजी औद्योगिक पार्क

राज्य मुख्यालय | आनंद सिन्हा

बरसों से बंद पड़ी प्रतापगढ़ की ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड की वीरान हो चुकी बेशकीमती जमीन अब जल्द ही आबाद होगी। जी हां, प्रदेश का औद्योगिक विकास विभाग ऑटो टैक्टर लिमिटेड फैक्ट्री की 97 एकड़ जमीन पर निजी इंडस्ट्रियल पार्क को विकसित करेगी।

इसके लिए यूपीसीडा बोर्ड ने प्रस्ताव पास कर लिक्विडेटर के पास बकाये के करीब 67 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए पत्र भेज दिया है। सरकार जल्द ही इसके लिए टेंडर करेगी। माना जा रहा है कि इससे प्रतापगढ़ और आसपास के इलाके के करीब 20 हजार युवाओं को रोजगार मिलेगा।दरअसल, प्रतापगढ़ की आटो टैक्टर लिमिटेड फैक्टरी वर्ष 1972 में बंद हो गई थी। बाद में तत्कालीन मुलायम सिंह सरकार ने वर्ष 1989 के करीब फैक्ट्री को सिपाही समूह के सुपुर्द कर दिया। कंपनी को फैक्ट्री का सिर्फ संचालन दिया गया था लेकिन फैक्ट्री चल नहीं सकी और बैंकों के कर्ज और कर्मचारियों के बकाये के चलते लिक्विडेटर द्वारा फैक्ट्री की जमीन फंसी पड़ी थी। प्रतापगढ़ के भाजपा सांसद संगमलाल गुप्ता ने करीब एक वर्ष पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर औद्योगिक विकास विभाग के अधिकारियों से मुलाकात कर पूरे प्रकरण की गहन जानकारी दी।

97 एकड़ जमीन पर निजी औद्योगिक पार्क विकसित होगा

67 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए पत्र भेजा गया

ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड

करीब चार दशक पहले इसका निर्माण हुआ था। यहां पर प्रताप ट्रैक्टर और आटोलैंड इंजन का निर्माण होता था। तत्कालीन विदेश मंत्री राजा दिनेश सिंह के प्रयासों से यह फैक्ट्री खुली और हजारों लोगों को इससे रोजगार मिला था।

प्रस्ताव का अध्ययन

औद्योगिक विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि यूपीसीडा ने पूरे प्रस्ताव का अध्ययन कर निर्णय किया है कि प्रतापगढ़ की यह जमीन चूंकि यूपीसीडा की ही थी, लिहाजा इसे वापस लिया जाएगा।

क्यों है उपयोगी

- प्रतापगढ़ अथवा प्रयागराज में इसके समान इतनी बड़ी जमीन उपलब्ध नहीं है।
- करीब में 220 केवीए का विद्युत पावर स्टेशन भी कैंपस में स्थित है।
- यह दो तरफ से अयोध्या-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग और लखनऊ-वाराणसी राजमार्ग भी इससे लगा है।
- साथ ही रेलवे स्टेशन करीब है। कच्चे माल को ढोने आदि में होगी सहूलियत
- सहयोगी इकाइयां भी स्थापित होंगी, 50 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।